

## मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्र-परिषद के नरिणय

### चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में वदियुत वतिरण कंपनयिों के लयि 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण मदीं में स्वीकृति दी गई।

### प्रमुख बदि

- प्रदेश में 33 सर्वसुवधायुक्त वदियालयों के लयि अनुमानति लागत 1335 करोड़ 20 लाख रुपए में नरिमाण कयि जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राज्ज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शकिषा वभिाग द्वारा 275 वदियालय वकिसति कयि जा रहे हैं।
- मंत्रपरिषद द्वारा वतितीय वर्ष 2023-24 के लयि नरिधारति दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लयि 'अटल गृह ज्योति योजना' में स्वीकृत सब्सिडी एवं वभिनिन उपभोक्ता श्रेणयिों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में वदियुत वतिरण कंपनयिों को वभिनिन श्रेणयिों में 24 हज़ार 196 करोड़ 47 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृति दी गई।
- मंत्र-परिषद ने प्रदेश के समस्त नगरीय नकियाओं में अधो-संरचना वकिस के लयि 'मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना वकिस योजना' चतुर्थ चरण को दो वर्षों (वतितीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) के लयि 1700 करोड़ रुपए की राशा की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्र-परिषद द्वारा खरगोन, धार, भडि, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी ज़िलों में 100 एम.बी.बी.एस सीटों की प्रवेश क्षमता वाले नवीन चकित्सा महावदियालय स्थापति कयि जाने के लयि सैध्नातिक सहमति प्रदान की गई है।
- 'दीनदयाल रसोई योजना' में पूर्व में स्थापति 100 रसोई केंद्रों के अतरिकित, 20 नवीन स्थायी रसोई केंद्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लयि जो स्थायी रसोई केंद्रों पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लयि 16 नगर नगिमाँ तथा पीथमपुर एवं मंडीदीप में कुल 25 नवीन चलति रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केंद्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रतिवियकृति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का नरिणय मंत्र-परिषद द्वारा लयिा गया है।
- मंत्र-परिषद द्वारा केंद्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचति कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ नरिशरति शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का नरिणय लयिा गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 (वपिणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जति ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी नरिशरति शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
- मंत्र-परिषद द्वारा सीप-अंबर कामप्लेक्स सचिाई परियोजना फेस-2 लागत राशा 190 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर ज़िले की भैरूदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हज़ार 457 हेक्टेयर सैच्य क्षेत्र में सचिाई सुवधि का लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त, 2013 से संचालति 'मध्य प्रदेश पुलसि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' को 31 मार्च, 2019 के पश्चात् से नरितर बनाए रखते हुए आगामी पाँच वर्ष तक नरितर संचालति कयि जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्र-परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परपितर खंड छ. क्रमांक 4 के परशिषिट-1 (एक) (ख) की तालकिा में केले की फसल हानिपर वर्तमान में आर्थकि अनुदान सहायता के लयि नरिधारति मापदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- केले की फसल में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर 30 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशा, 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 54 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशा एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशा किरने की स्वीकृति दी गई।
- आर्थकि अनुदान सहायता राशा की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रुपए के स्थान पर 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।